चौटाला साहब ने घोटाला किया तो क्या गलत किया

फिर से हरियाणा की सत्ता पर काबिज़ होने का सपना देखने वाले इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला इस बुढ़ापे में अपने पुत्र के साथ तिहाड़ जेल में कैद हो गए। शर्मनाक। पता नहीं, ताऊ देवीलाल की आत्मा का क्या हाल हो रहा होगा। वैसे, वो भी 'धृतराष्ट्र' से कम नहीं थे। चौटाला उस वक्त जेल भेजे गए हैं, जब हुड्डा सरकार संकट में है। पर कांग्रेसी जोड़-तोड़ कर, दल-बदल करबा, रिश्वत आदि दे संकट से निकलने में माहिर हैं। हुड्डा साहब ने भी ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है और इसके लिए सोनिया इनकी पीठ ठोकेंगी। चौटाला के जेल जाने से कांग्रेस में खुशी की ऐसी लहर है जो पहले कभी नहीं देखी गई। हुड्डा साहब को लगता है कि उन्होंने अपने सबसे बड़े विरोधी को चित कर दिया।

चौटाला और उनके कुनबे पर आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले पहले से ही चल रहे हैं। पर अब इसे बड़ा मामला नहीं माना जाता। राज्य में जितने नेता हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विरोधी के, अगर उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए तों सभी पर मामले बन सकते हैं। अपवादस्वरूप कुछ को छोड़ दिया जाय तो तमाम आला अफ़सरों का भी यही हाल है।

हुड्डा मंत्रिमंडल में ऐसे-ऐसे डाकू, औरतों की इज्ज़त से खेलने वाले और अपराधी शामिल हैं, जिनके वारे में कौन नहीं जानता! पर अभी बुरा वक़्त है चौटाला का, सो तिहाड़ जाना पड़ा। हुड्डा के लिये भी बुरा वक़्त जल्दी ही आने वाला है। यह साल देखते-देखते बीत जायेगा। और फ़िर 2014। 2014 का ख़्याल जब आता है सोनिया से लेकर तमाम छोटे-बड़े कांग्रेसियों के पसीने छूटने लगते हैं। दिल को बहलाने का कोई अच्छा-सा ख़्याल नहीं आता। तो अल्ला की मर्जी। ख़ुदा-ख़ुदा करके काट लिए घोटालों भरे पांच साल, लूट-लूट कर घर भर लिया सबों ने तो आगे की भी ख़ुदा ही जानेगा। भाजपा राम-राम करेगी, कांग्रेस अल्ला-ओ अकबर। मुसलमानों को पटाना है। जय हो। जय हो भारत। 'अतुलनीय' भारत। बहरहाल, हम विषय से भटक गए। सवाल चौटाला साहब के जेल जाने का है। यह मामला संगीन है। ताऊ देवीलाल के खानदान के बड़े नाम पर बट्टा लग गया।

चौटाला ने देश के अमीर राज्यों में शुमार हरियाणा पर जब शासन किया तो लट्ठ के जोर पर ही किया। हर महकमे से मंथली वसूली।

व्यापारी हों या उद्योगपति, किसी को नहीं छोड़ा। किसी ने दाएं-बाएं कर हैवी वसूली से बचने की कोशिश की तो उसे मां-बहनों की गालियां सुननी पड़ी स्वयं चौटाला के श्रीमुख से। मां-बहन की गालियां देने के मामले में इनके पिता ताऊ चौधरी देवीलाल भी कम नहीं थे। जब वो इस देश के उप-प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किसी बात पर नाराज़ होकर 'द इंडियन एक्सप्रेस' के तत्कालीन एडिटर-इन-चीफ़ अरूण शौरी को फ़ोन पर गंदी-गंदी गालियां दी थीं, जिसे शौरी ने दूसरे ही दिन अख़बार में ज्यों का त्यों छाप दिया था। पर इससे ताऊ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चौटाला साहब की पहचान देश में 'महम कांड' से भी है। गुंडागर्दी में चौटाला साहब का कोई सानी नहीं है। उनकी पार्टी में एक से बढ़कर एक गुंडा रत्न भरे हुए हैं। इन्होंने हरियाणा की राजनीति को लट्ठ से चलाया, पर अब इनका सूरज अस्तांचल की ओर बढ़ चला है। इनके बेटों में वो दम नहीं जो अपने बूते राजनीति में दो डग भी चल पाएं।

फिलहाल, चौटाला यह मंसूबा पाल रहे थे कि इस बार जब हरियाणा विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस किसी हाल में सत्ता में नहीं आ सकती, फिर तो मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाना है।

चौटाला का यह आकलन गलत नहीं था। अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसी हाल में सत्ता में नहीं आ सकती। हरियाणा जनहित कांग्रेस और भाजपा की हालत बुरी है। कुलदीप की पार्टी के कई विधायक सत्तापक्ष में चले गए और वह हाथ मलते ही रह गए।

ऐसे में, चौटाला के पक्ष में समीकरण बन रहे थे। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। महाभ्रष्टों में से ही जनता को किसी न किसी को चुनना है ताकि जनतंत्र की नौटंकी चलती रहे। जनता के लिए यह नौटंकी जरूरी तो नहीं, पर लीडरों के लिए जरूरी है।

लूट-खसोट, बलात्कार, छीना-झपटी, मर्डर आदि लीडरों के 'राष्ट्रीय कर्त्तव्य एवं अधिकार' हैं। घोटाले करना तो परमाधिकार है। अगर टीचर भर्ती में चौटाला ने घोटाला किया तो गलत क्या किया। हाँ, इस आरोप में चौटाला की सैपुत्र गिरफ़्तारी ग़लत है। सरकार को समझना चाहिए, चौटाला बुर्जुग हैं, साथ ही 'विक्लांग' भी। लाठी के सहारे बिना चल नहीं सकते। उन्होंने घोटाला किया तो कांग्रेसियों ने उनसे कम घाटाले नहीं किए। भाजपाई भी जब केंद्र की सत्ता में रहे तो खूब घोटाले किए। चौटाला ने तो मामूली टीचर भर्ती घोटाला किया है। राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार हो, हमारा मानना है, चौटाला ने इसी जनहित की दृष्टि से घोटाला किया होगा।

सरकार ने उन्हें बदले की भावना से गिरफ़्तार कराया है।

बहरहाल, जब गिरफ़्तार कर ही लिया तो अब इन्हें पूरे आराम के साथ रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। सारी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। हरियाणा के पुराने जमीन्दार घराने के हैं, जेल में शाही अंदाज में इनका आतिथ्य होना चाहिए।

चौटाला ने घोटाला किया तो क्या और नेताओं ने नहीं किया? सज़ा होती हो तो सबको हो। और सज़ा क्यों हो? संविधान में एक संशोधन हो, घोटाला किया जाना अपराध हर्गिज़ न माना जाये। होना तो यह चाहिए कि जो लीडर घोटालें करने में कोई विशेष कीर्तिमान आदि स्थापित करें, उनके लिए राष्ट्रीय स्तर के किसी विशेष सम्मान की घोषणा की जानी चाहिए।

-ग़रीबदास

चौटालों को कैद का राजनीतिक प्रभाव

हरियाणा की हुड्डा सरकार पिछले 8 वर्षों से जिस तरह चल रही है उसने चौटालों की राह स्वत: सरल बना दी थी। नाकारा सरकारी मशीनरी, लचर प्रशासनिक व्यवस्था, भ्रष्ट एवं निकम्मे अधिकारियों को प्रथमिकता तथा लूट-खसूट की खुली छूट ने जनता की तमाम आशाओं पर पानी फ़ेर दिया। चौटालों के कुशासन से आहत जनता ने कांग्रेस पर दाव लगाया था, लेकिन इनके कुशासन ने चौटाला राज को बेहतर कहलवा दिया। हुड्डा सरकार के कुकृत्यों को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में धारणा यहां तक बन गयी कि सत्ता प्राप्त करने के लिये अब चौटालों को कुछ खास करने की जरूरत नहीं क्योंकि हुड्डा साहब स्वंय थाली में सजा कर सत्ता उन्हें सोंपने जा रहे हैं।

रही बात कुलदीप की हजकां पार्टी की तो इसे अभी तक कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। राजनीति के व्यवसाय में इनके पिता भजन लाल द्वारा लूटा गया अपार धन जो इनको विरासत में मिला है उसी की बदौलत ये अपनी पार्टी का ढोल बजा रहे हैं। राजनीतिक विचारक मानते हैं कि कुलदीप ने पिता का धन तो प्राप्त कर लिया लेकिन उनकी राजनीतिक सूझ-बूझ तथा किस मौके पर क्या करना है, जैसी कलाकारी से अभी कोसों दूर हैं।

जाने अनजाने हुड्डा तो अपना यह काम कर ही रहे थे परन्तु अदालती फ़ैसले ने उक्त प्रक्रिया पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सवाल अब यह खड़ा हो गया है कि क्या चैटाला हुड्डा की थाली स्वीकार कर पाने का स्थिति में बचें हैं? कुछ लोगों का मानना है कि चौटालों को हुई कैद से उनके प्रति सहानुभूति की ऐसी लहर चल सकती है जिस पर सवार हो कर वे सत्ता की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके आसार न के बराबर होते हुए भी कांग्रेसी कुशासन से पीड़ित जनता अपने आपको विकल्पहीनता की स्थिति में पा रही हैं। कांग्रेस व चौटाला पार्टी के बाद बचता है भाजपा व हजकां गठबंधन। इन दोनों ही पार्टियों की जनता में पकड़ को प्रभावी नहीं माना जाता। राज्य के मात्र कुछ भागों में इनका थोड़ा बहुत असर है। सत्ता रूढ होने के लिये जनमानस पर जिस व्यापक पकड़ की जरूरत होती है उसका नितांत अभाव है। भाजपा के पुरज़ोर प्रयासों के बावजूद भी इसकी पकड़ शहरों के बाहर बसी ग्रामीण जनता में ना के बराबर है जबकि बहुमत इसी जनता का है। इसके अलावा सांप्रदायिक लेबल तो इस पर सदा से चस्पा है ही। रही बात कुलदीप की हजकां पार्टी की तो इसे अभी तक कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। राजनीति के व्यवसाय में इनके पिता भजन लाल द्वारा लूटा गया अपार धन जो इनको विरासत में मिला है उसी की बदौलत ये अपनी पार्टी का ढोल बजा रहे हैं। राजनीतिक विचारक मानते हैं कि कुलदीप ने पिता का धन तो प्राप्त कर लिया लेकिन उनकी राजनीतिक सूझ-बूझ तथा किस मौके पर क्या करना है, जैसी कलाकारी से अभी कोसों दूर हैं।

इन हालात में लगता नहीं कि 2014 के चुनावों में कोई एक दल अथवा गठबंधन स्पष्ट बहुमत ले पायेगा। ऐसे में निर्दलीय की संख्या में अधिक बढोतरी होना तय है जिन्हें खरीद पाने में सत्तारूढ दल सदैव सक्षम रहता आया है।

पेड न्यूज़ : धंधा जारी रहेगा

पेड न्यूज़ का मामला अब कुछ ज़्यादा ही गंभीर होता जा रहा है। इस मामले का संज्ञान भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भी लिया है।

दरअसल, पेड न्यूज़ का मामला आज का कोई नया मामला नहीं है। मीडिया जगत में यह खेल बहुत पहले से चल रहा है। इस खेल में ऊंची-ऊंची तनख्वाहें पाने वाले बड़े संपादक और पत्रकार शामिल रहे हैं। यह बात स्पष्ट है कि बिना मालिकान की स्वीकृति के अख़बारों में एक शब्द भी नहीं छप सकता और न ही टीवी चैनलों पर कोई ख़बर दिखाई जा सकती है। पहले पेड न्यूज़ का मामला बड़े ही दबे-छुपे रूपों में चलता था। पर अब यह खुलेआम चल रहा है। यह खेल अपने पूरे शबाब पर तब होता है जब किसी राज्य अथवा केंद्र में चुनाव हो रहे होते हों। इसके अलावा नेताओं की छवि बनाने-बिगाड़ने के लिए यह खेल चलता है।

पहले यह काम इतने गोपनीय रूप से किया जाता था कि किसी को ख़बर तक नहीं लग पाती थी। पर पत्रकारिता के स्तर को गिराने में इस खेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। किसी नेता अथवा पार्टी के पक्ष में पूरा प्रचार अभियान और अन्य पार्टियों अथवा नेताओं को हाशिये पर भी जगह नहीं देने से धीरे-धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि कहीं यह पैसों के लेन-देन से जुड़ा मामला तो नहीं है। सबसे पहले 'जनसत्ता' के पूर्व संपादक और संपादकीय सलाहकार की भूमिका निभा रहे स्व.प्रभास जोशी ने इस मामले को उठाया था। इसके बाद 'द हिंदू' के वरिष्ठ पत्रकार पी.साईनाथ ने महाराष्ट्र में अशोक चव्हान द्वारा पत्रकारों को पैसे देकर अपने पक्ष में ख़बरें छपवाने के मामले को सप्रमाण उजागर कर दिया। इससे यह साबित हो गया कि मीडिया जगत में पैसा स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह बनाने की भूमिका निभा रहा है। यानी पत्रकारों को पैसे देकर अपने पक्ष में और विरोधियों के विपक्ष में ख़बरें आसानी से छपवाई जा सकती हैं। इससे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया की साख पर ख़तरा उपस्थित हो गया। ख़बरों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेड न्यूज़ का मामला सिर्फ़ पत्रकारों तक ही सीमित नहीं है। सर्वशक्ति संपन्न सत्ताधारी सीधे अख़बारों के मालिकान से ही संपर्क करते हैं और मालिकान के आदेश पर संपादकों को ख़बरें प्रकाशित-प्रसारित करनी पड़ती हैं। इसके बदले मालिकानं को मोटा माल मिलता है। विज्ञापन लेना तो उनका अधिकार है ही। इन हालात में पेड न्यूज़ की बीमारी के लिए सिर्फ़ पत्रकारों को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

इसके लिए पूरी तरह से मीडिया संचालक दोषी हैं। अगर मीडिया संचालक इस मामले में पाक-साफ़ होते तो पत्रकारों में पैसे लेकर ख़बरें छापने की प्रवृत्ति पैदा नहीं होती। पहले पत्रकार खा-पीकर ही संतुष्ट हो जाया करते थे। बाद में उन्हें कुछ उपहार भी मिलने लगे। पर ख़बरें छापने के लिए पैसे का लेन-देन चलन में नहीं आया था। पूंजीवादी मीडिया ने अपनी एक मर्यादा कायम रखी थी। तमाम अख़बारों और पत्रिकाओं के जो संपादक हुआ करते थे, अधिकतर वे उच्च कोटि के साहित्यकार थे और कइयों ने तो विश्वविद्यालयों में प्रतिष्ठापूर्ण पदों को छोड़ कर पत्रकारिता को अपनाया था। उनकी एक सुस्पष्ट विचारधारा थी, जनहित से वे प्रतिबद्ध भी थे और पूंजीवादी घरानों की पत्रकारिता में उन्होंने रचनात्मकता के एक से बढ़ कर एक कीर्तिमान स्थापित किये। सरकार की ग़लत नीतियों का विरोध वे डंके की चोट पर करते थे। वह एक अलग दौर था।

पर पिछले 20 वर्षों के दौरान समाज में बाज़ारवादी व्यवस्था का जिस स्तर पर विस्तार हुआ, उससे मीडिया जगत भी नहीं बच सका। इस बाज़ारवादी व्यवस्था में हर चीज़ बिकाऊ हो गई। कुछ भी ऐसा न रहा जो खरीदा-बेचा न जा सके। फ़िर ख़बरें क्यों न खरीदी-बेची जातीं?

हुड्डा साहब ने बनवाई आंख

रोहतक (म.मो.) गत सप्ताह भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अपनी एक आंख के मोतिया बिंद का आप्रेशन किया। हरियाणा को चिकित्सा का हब बताने वाले हुड्डा साहब को अपने राज्य में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जंचा जहां वे यह आप्रेशन करा सकते। इसके लिये उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती होना पड़ा। उनके रोहतक स्थित अपने घर की बगल में ही 60 साल पुराना मेडिकल कालेज एवं अस्पताल है। यहां से आंख बनवाना उन्होंने उचित नहीं समझा। इसका असल कारण उस संस्थान की ख़स्ता हालत है। कुप्रबन्धन के चलते वहां कोई भी इलाज कराना खतरे से खाली नहीं। पिछली सरकारों के वक्त से चले आ रहे कुप्रबन्धन को दुरूस्त करने की अपेक्षा, इन्होंने इसको और बढावा दिया है। रोहतक मेडिकल कॉलेज में ना सही अपने राज्य के किसी तो सरकारी अस्पताल में वे यह काम कराने की हिम्मत दिखाते। जाहिर है वे अपने अस्पतालों की स्थिति एवं दुदर्शा से पूर्णतया परिचित हैं। इसलिये वे ऐसा जोखिम नहीं ले सकते थे। राज्य के किसी प्राइवेट अस्पताल में वे इसलिये नहीं गये कि इससे उनके सरकारी अस्पतालों की दुदर्शा और भी अच्छी तरह प्रमाणित हो जाती। अब वे कह सकते हैं कि उन्होंने तो सरकारी अस्पताल में ही आप्रेशन कराया है चाहे दिल्ली के ही सही। विदित है कि मोतिया बिंद का आप्रेशन एक अति साधारण आप्रेशन माना जाता है। राज्य का दुर्भाग्य है कि इतनी सरल सी चिकित्सा का भी राज्य में प्रबन्ध नहीं है जिसे चिकित्सा का हब बताते हुए मुख्यमंत्री कभी थकते नहीं।